



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उद्देश्य पूर्ति में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका

—शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता— 1—सुधीर चन्द्र नौटियाल, शोधार्थी, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून,
2—डा० शिव कुमार श्रीवास्तव, एसो. प्रो., स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून

सारांश—

विश्व के लगभग सभी देशों में शिक्षा एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिसे अपने उस देश के राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक तरीके से संचालित, संवर्धित किया जाता है और साथ ही आधुनिकतम बनाने के प्रयास भी चलते रहते हैं। हमारे देश भारत में भी प्राचीन काल से ही समृद्ध शिक्षण और प्रशिक्षण (शिक्षा—दीक्षा) की परम्परा रही है जो समय के साथ अपने स्वरूप बदलते हुए आश्रम पद्धति से चलकर विद्यालयी और संस्थागत शिक्षा के रूप में वर्तमान में गतिमान है। हमारे देश में अधिकतर शासकों ने इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर जन सामान्य तक सामान्य शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किये व साथ ही उच्च शिक्षित विद्वानों और विविध कलाओं को संरक्षण देकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के प्रयास किये। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया और इसका स्तर बढ़ाने एवं सुधार के प्रयासों के अंतर्गत कुछ समय के अंतराल के उपरान्त हमारी तीन शिक्षा नीतियां सामने आईं। इनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वाधिक आधुनिक है व वर्तमान में अपने प्रस्तावों पर चर्चा और क्रियान्वयन के क्रम में चलन में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा समाज के सभी वर्गों में शिक्षा पहुंचाने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ाने, स्वरूप बदलने और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने सम्बन्धी अनेक उद्देश्य रखे गये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये हैं जो सहज ही आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित हैं और अनेक प्रारूपों में दूरस्थ शिक्षा से साम्यता भी रखते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में दूरस्थ शिक्षा का अधिकांश स्थानों पर उल्लेख नहीं है तथापि यदि इस पर योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाय तो यह नई शिक्षा नीति के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वाधिक सक्षम माध्यम हो सकता है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उद्देश्यपूर्ति हेतु दिए गये प्रस्तावों में दूरस्थ शिक्षा से साम्यता रखने वाले उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है व इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व इसकी उद्देश्य पूर्ति में दूरस्थ शिक्षा के उपागमों पर चर्चा की गयी है व इस हेतु अंतराल ढूँढने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना:

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 दूरस्थ शिक्षा के प्रावधानों सहित शिक्षा में तकनीकी एवं शिक्षण के एकीकरण पर जोर देती है। एनईपी 2020 शिक्षा को व्यापक आबादी तक पहुंचाने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सीखने, प्रौद्योगिकी के उपयोग और ऑनलाइन शिक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अधिकतर प्रावधानों में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। इस नीति के अंतर्गत स्वयं दूरस्थ शिक्षा के विकास की भी बात की गई है किन्तु साथ ही एक पहलू यह भी है कि दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की अभी हमारे देश में अनेक सीमायें भी हैं इनके प्रति अभी समझ एवं स्वीकार्यता में भी कार्य की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में स्वयं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र के विकास की बड़ी आवश्यकता होगी।

मुख्य शब्द: दूरस्थ शिक्षा, प्रौद्योगिकी, ODL, NEP 2020.

शोध के उद्देश्य-

प्रस्तुत षोधपत्र के उद्देश्य हैं-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा के उद्देश्यों में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा माध्यम को प्रभावी माना गया है उन्हें प्रस्तुत करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य में दूरस्थ शिक्षा के प्रभावी उपयोग हेतु चुनौतियों का अध्ययन करना।

डाटा संग्रह: षोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से डाटा संग्रह किया गया है। प्रस्तुत षोध पत्र इन स्रोतों से प्राप्त अध्ययन सामग्री का विष्लेषण करके लिखा गया है।

1- प्राथमिक स्रोत: इस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिंदी संस्करण के मूल पाठ का प्रयोग किया गया है जो भारत सरकार द्वारा जारी है।

2- द्वितीयक स्रोत: इस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित लेख अध्ययन व षोध पत्र हैं जिनका अध्ययन इस षोध पत्र के उद्देश्यों के संदर्भ में किया गया है। इस पत्र के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप यह अल्प मात्रा में उपलब्ध है।

साहित्यावलोकन-

1. बिरेंद्र सिंह 2. कुकन देवी © 2022 IJRAR January 2022, Volume 9, Issue 1 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा मान्यता सम्बन्धी नियमों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों के पास इस सम्बन्धी विकल्प होगा, यदि वे दूरस्थ माध्यम से अपने कोई कोर्स चलाने की मान्यता रखते हों, तो इससे वे अपने कार्यक्रमों का प्रसार कर पायेंगे, छात्र नामांकन बढ़ा पायेंगे एवं अपने शिक्षार्थियों के वय वर्ग में सुधार करके उन्हें आजीवन सीखने के अवसर प्रदान कर पायेंगे।

2. Dr. Rupesh G. Sawant, Dr. Umesh B. Sankpal © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा के नामांकन बढ़ाने सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति में ओ.डी.एल. अर्थात् मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं इस सम्बन्ध में उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किये गये ऑनलाइन शिक्षा व ओ.डी.एल. सम्बन्धी प्रावधान काफी महत्वपूर्ण हैं।

विश्लेषण:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक स्थानों पर डिजिटल तकनीक एवं शिक्षा के दूरस्थ माध्यमों का सीधे-सीधे उल्लेख है व कहीं-कहीं किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति में इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली तकनीकों का अपरोक्ष रूप से भी प्रयोग की भी बात की गई है। स्पष्टतः नई शिक्षा नीति अपनी उद्देश्यपूर्ति में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावी मानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रयुक्त डिजिटल व दूरस्थ शिक्षा तकनीकों को निम्नवत दिया जा सकता है-

1. ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग: नीति ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के महत्व को पहचानती है और शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है। इस कदम के तहत दीक्षा पोर्टल का विकास, पी.एम.ई विद्या व स्वयंप्रभा के अंतर्गत फ्री शैक्षिक टी.वी.चैनल के माध्यम से शिक्षण जैसे अनेक प्रयास सम्मिलित हैं। इनसे निश्चित ही ATE(Any Time Education)/ किसी भी समय शिक्षा जैसे विचार को बल मिलता है व शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF): शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस मंच से निर्णयकर्ताओं, प्रशासकों और शिक्षकों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद है।

3. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL): NEP 2020 उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर देता है, विशेषकर ऐसे लोग के लिए जो पारंपरिक तरीकों से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा अपने कार्य एवं व्यवसाय के साथ अपनी शिक्षा को भी जारी रखना चाहते हैं। दूरस्थ शिक्षा में

ऐसे भी अनेक कोर्स उपलब्ध होते हैं जो समाज की तत्समय की आवश्यकता पर आधारित होते हैं व जो पारम्परिक शिक्षा में उपलब्ध नहीं होते।

4. ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट बैंक: शिक्षा नीति 2020 एक क्रेडिट बैंक की स्थापना का सुझाव देती है, जहाँ छात्र ऑनलाइन लिए गए पाठ्यक्रमों के लिए भी क्रेडिट जमा कर सकते हैं। इन क्रेडिट को नियमित शैक्षणिक प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे पाठ्यक्रम और संस्थानों को चुनने में लचीलापन बढ़ेगा। यह नीति वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा में भी प्रचलित है। इससे शिक्षार्थियों को कार्यक्रमों के बीच क्रेडिट स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है।

5. शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: एनईपी 2020 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर देता है। यह भी दूरस्थ शिक्षा का एक उपागम है।

6. एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु: एनईपी 2020 एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और छात्रों को विभिन्न चरणों में शिक्षा में प्रवेश करने और उत्तीर्ण करने की अनुमति देने का सुझाव देता है। यह लचीलापन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के के तौर-तरीकों से प्रेरित है, जहाँ शिक्षार्थियों को अक्सर अपनी गति और अध्ययन की अवधि चुनने का लचीलापन होता है।

7. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) को बढ़ावा देना:

- NEP 2020 उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर देता है। इस नीति में राज्यों के अपने मुक्त विद्यालय व मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। इससे निश्चित ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं व्यापक पहुँच के उद्देश्य पूर्ण होंगे।

8. शिक्षक प्रशिक्षण और सतत व्यावसायिक विकास:

- एनईपी 2020 शिक्षक प्रशिक्षण और सतत व्यावसायिक विकास के लिए तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करता है। यह दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए अधिक प्रासंगिक है जो शिक्षकों के लिए खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करते हैं। किंतु साथ ही ध्यान देने योग्य है कि एनईपी 2020 में दोहरी शिक्षा पद्धति वाले विश्वविद्यालयों की बात की गई है अर्थात् एक ही विश्वविद्यालय परिसर में पारम्परिक एवं दूरस्थ दोनों माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने के विकल्प होंगे। ये उस वर्ग के लिये महत्वपूर्ण है जो किसी भी निजी अथवा व्यवसायिक कारण से पारम्परिक शिक्षा में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं कर पाता एवं अपने उपलब्ध समय के अनुसार अध्ययन करना चाहता है।

NEP 2020 के दूरस्थ शिक्षा प्रावधानों से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ— यद्यपि दूरस्थ शिक्षा 1986 से भारत में अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आनी शुरू हो गयी थी इसमें आने वाले समय के साथ हमेशा मजबूती आती गई। इसी मजबूत स्वरूप और समय की मांग के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में भी वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पर विश्वास जताया गया है। इस सब के बाद भी आज तक हमारे समाज में दूरस्थ शिक्षा के प्रति समझ और स्वीकार्यता का अभाव है। वर्तमान में भारत में NEP 2020 के दूरस्थ शिक्षा प्रावधानों से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नवत दी जा सकती हैं—•

1. बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी: भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियाँ हो सकती हैं। यह दूरस्थ शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल संसाधनों तक पहुँच सीमित है।

2. डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता के स्तर में एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हो सकता है, खासकर कुछ जनसांख्यिकी के बीच। छात्रों और शिक्षकों को सीखने और सिखाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

3. न्यायसंगत पहुँच: गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ शिक्षा तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को आवश्यक उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

4. गुणवत्ता आश्वासन: दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पारम्परिक/भौतिक रूप से कक्षा के माहौल की अनुपस्थिति में सामग्री, मूल्यांकन और समग्र सीखने के अनुभव की गुणवत्ता से संबंधित चिंताएँ हो सकती हैं। इस हेतु प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग व प्रभावी माध्यम के निर्माण की आवश्यकता है।

5. शिक्षक प्रशिक्षण: प्रभावी दूरस्थ शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है। NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को पचानती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षक इसका लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। अतः दूरस्थ शिक्षा के प्रति अभिमुखीकरण एवं इसके प्रभावी उपयोग के तौर तरीके सीखने हेतु प्रशिक्षण न केवल शिक्षकों को इसके उपयोग हेतु तैयार करेगा बल्कि समाज के दूरस्थ शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव भी लायेगा।

6. मूल्यांकन और मूल्यांकन की प्रक्रिया: दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय तरीके तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छात्रों के शारीरिक रूप से मौजूद न होने पर परीक्षाओं और मूल्यांकन की अखंडता सुनिश्चित करना कुछ कठिनाइयाँ पैदा करता है।

7. मान्यता और स्वीकृति: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित डिग्री की मान्यता और स्वीकार्यता के बारे में चिंताएँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कुछ पेशेवर क्षेत्रों में। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नियोक्ता और संस्थान दूरस्थ शिक्षा प्रमाणपत्रों के मूल्य को पहचानें।

8. सहभागिता और जुड़ाव: आभासी वातावरण में छात्र जुड़ाव बनाए रखना और बातचीत को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सहयोगात्मक शिक्षण अनुभव और छात्र-शिक्षक बातचीत को प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

9. केंद्र व राज्य स्तर पर नीति कार्यान्वयन: जबकि NEP 2020 राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपरेखा प्रदान करता है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन केंद्र से राज्य व राज्य से राज्य-स्तरीय पहलों पर भी निर्भर करता है। केंद्र एवं राज्यों में अथवा राज्यों में आपसी समन्वय और स्थिरता एक चुनौती हो सकती है।

निष्कर्ष :

भारत में दूरस्थ शिक्षा सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरान्त प्रभावी रूप से लागू हुयी और वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में प्रयोग होने वाले अनेक तौर तरीकों और शिक्षण विधियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हुआ है। नई शिक्षा नीति में परम्परागत माध्यम से चलने वाले विद्यालयीय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों हेतु तकनीक व प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अनिवार्य किया गया है। किन्तु इन तौर तरीकों व अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करना होगा व उन्हें स्वयं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु अवसर भी प्रदान करने होंगे। इसके सम्बन्ध में नीतियों पर कार्य एवं संसाधनों की व्यवस्था दोनों महत्वपूर्ण हैं, और इससे भी मुख्य है स्वयं दूरस्थ शिक्षा पर अकादमिक कार्य जिससे इसकी स्वीकार्यता बढ़ सके। एक और चीज यहां महत्वपूर्ण लगती है, और वह है दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखना जिससे ये उद्योग जगत व अन्य रोजगार के क्षेत्रों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. Ministry of Education, Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Retrieved from https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_
2. Mahesha, V., Niranjana Raju, S., & Rajeshwari, H. (2023). *SIRJODL*, 5(1&2). ISSN 2582-9009.
3. Shukla, P. D., & Kaur, J. (2021). A study on the impact of National Education Policy 2020 on higher education system. *Journal of Education and Practice*, 12(16), 94-100.
4. National Education Policy 2020: A game-changer for Indian education (2021). *Journal of Education and Practice*, 12(3), 1-8.
5. Jha, J. (2017, June 13). *Journal of Learning for Development*.